चीन की सामाजिक विज्ञान अकादमी में प्रधानमंत्री का भाषण

15 जनवरी, 2008
पेइचिंग, चीन

चीन की प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान अकादमी की इस विशिष्ट सभा को सम्बोधित करते हुए मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आपकी यह संस्था बहुत ही अग्रणी संस्था है जिसने पिछले तीन दशकों में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया है और चीन के सुधार और विकास में बहुत योगदान दिया है।

इस महान देश में आकर मुझे प्रसन्नता हुई है। हम भारत में चीन द्वारा की गई उल्लेखनीय आर्थिक उन्नति की प्रशंसा करते हैं। चीन की प्रगति हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। चीन का सबसे बड़ा पड़ोसी और मित्र होने के नाते हम इस गतिशील प्रक्रिया से अछूते नहीं रह सकते।

चीन के महान विद्वान और हमारे समय के प्रमुख भारतविदों में से एक प्रोफेसर जी ज़ियानलिन ने ठीक कहा है और मैं उनके शब्दों को दोहराता हूं- दो महान सांस्कृतिक वृत्त-- चीन और भारत, ने एक दूसरे से हमेशा सीखा है और एक दूसरे को प्रभावित किया है और इस प्रक्रिया से दोनों संस्कृतियों का तेजी से विकास हुआ है। यह इतिहास भी है और वास्तविकता भी है।

आज भारत और चीन दोनों तेजी से हो रहे परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों में विकास का एजेंडा प्रमुख है। हमारी प्रणालियां भिन्न हैं, लेकिन बेहतर भविष्य की आकांक्षा के साथ दोनों देशों के लोग एक हैं। जब चीन और भारत जैसे बड़े आकार के देश, जहां ढाई अरब लोग रहते हैं, अपनी रचनात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढते़ हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। दुनिया यह जानती है और बहुत दिलचस्पी के साथ इसे देख रही है।

इसलिए मैं इस अवसर पर भारत के विकास के अनुभवों के बारे में कहना चाहूंगा। और यह भी कि मैं इसे भारत और चीन के लिए 21वीं सदी में मिलकर काम करने के एक विशेष अवसर के रूप मे देखता हूं।

प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने पिछले दिनों सिंगापुर में कहा था कि किस तरह खुलेपन और समग्रता के दृष्टिकोण के साथ देश मजबूत और खुशहाल बन सकता है। पिछले कुछ दशकों में अपनी अर्थव्यवस्था बाकी विश्व के लिए खोल देने से चीन को बहुत लाभ हुआ है। और भारत ने भी ऐसा ही किया है।

भारत बदल रहा है और मैं यह कहना चाहूंगा कि चीन की सफलता इस परिवर्तन के लिए प्रेरणा रही है। यह प्रक्रिया 1980 के वर्षों में शुरू हुई और 1991 में इसने जोर पकड़ा। हमारी प्रणाली में परिवर्तन सार्वजनिक बहस से ही लाया जा सकता है और राजनीतिक सहमति बनाने में समय लगता है। लेकिन मुझे खुशी है कि 1991 के बाद जो 16 वर्ष गुजरे हैं, इन वर्षों में भारत में एक, के बाद एक सभी सरकारों ने सुधार की प्रक्रिया को आगे बढा़या है, जिसका परिणाम यह है कि भारत अब तेजी से विकास के रास्ते पर है।

पिछले पांच वर्षों में भारत की औसत विकास दर लगभग 8.5 प्रतिशत वार्षिक रही है। यह अप्रत्याशित है और इसने हमारे अंदर विश्वास जगाया है कि हम और भी बेहतर कर सकते हैं। निकट भविष्य में हमारा लक्ष्य विकास दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत वार्षिक तक पहुंचाना है। देश में इस समय एक विश्वास का जज्बा है और भविष्य के बारे में आशावादिता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। पिछले दो दशकों में हमारे उद्योगों ने, विशेष रूप से बड़े और मझौले उद्योगों ने परिवर्तन किए हैं और वे अब विश्व स्तर पर स्पर्धा करने लगे हैं। यह प्रक्रिया जारी है।

पिछले कुछ वर्षों में हम ऐसा वातावरण बना पाएं हैं, जो सृजनात्मकता और उद्यमशीलता दोनों के लिए अनुकूल है। विश्व के बाजारों में हमारे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सफलता इस बात का प्रतीक है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जो सामने आ रहे हैं। औषधि निर्माण और ऑटो--कल-पुर्जों के क्षेत्र बहुत ही स्पर्धात्मक हैं। भारतीय बहु राष्ट्रीय कंपनियां उभरी हैं और विदेशों में निवेश कर रही हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता महसूस हो रही है कि इनमे से कई कंपनियां इस महान देश चीन में भी पूंजी निवेश कर रही हैं।

कुछ सप्ताह पहले हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद ने, जिसमें केन्द्र सरकार के अलावा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश भी हैं, भारत की 2007 से 2012 तक की 11वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना में विकास की गति को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि वर्ष 2012 तक विकास की दर 10 प्रतिशत तक पहुंच जाए। लेकिन योजना में इस बात पर भी गौर किया गया है कि केवल विकास ही योजना प्रक्रिया का लक्ष्य नहीं हो सकता।

हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास समग्र हो और समतापूर्ण हो। हमें अंतर-क्षेत्रीय असमानता और विशेष रूप से शहरी-ग्रामीण असमानता की समस्या, कृषि क्षेत्र के पुनरूद्धार, भूमि की सीमित उपलब्धता और कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को उद्योगों में उपयोगी रोजगार के लायक बनाने जैसी समस्याओं पर गौर करना है। समग्र विकास से हमारा मतलब यही है। यह लगभग वैसा ही है, जिसे चीन में सामंजस्य पूर्ण विकास कहा जाता है।

हमने योजना में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन करने का फैसला किया है ताकि हम जटिल बाधाओं पर ध्यान दे सकें, जो तेज तथा अधिक समग्र विकास के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के आड़े आती हैं। जहां तक विकास की बात है, सबसे बड़ी प्राथमिकता बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की होनी चाहिए। हमारा विचार, वर्ष 2012 तक बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत तक करना है, जो 2006 में 5 प्रतिशत था। इसमें सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के निवेश का लाभ उठाना है।

शिक्षा हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें विभिन्न कौशलों का विकास भी शामिल है। हमारी योजना, शिक्षा और कौशल विकास पर होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार के हिस्से को तीन गुना करके 11वीं योजना में कुल योजना व्यय के 19 प्रतिशत से भी ज्यादा करने की है, जो इस समय 8 प्रतिशत से भी कम है। वास्तव में कुल सरकारी बजट खर्च का आधे से ज्यादा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित है, जो समग्र विकास की हमारी आकांक्षा को दर्शाता है।

भारत के आकार जैसे देश के लिए विकास की गति की निरंतरता एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हमें ऊर्जा, खाद्यान्न और जल सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वूपर्ण चुनौतियों पर भी ध्यान देना है। ये चुनौतियां चीन के सामने भी हैं।

भारत की घरेलू और विदेश नीति की जो प्राथमिकताएं हैं, उनमें निकट संबंध है। हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा बाहरी वातावरण बनाना है, जो हमारे तेज विकास के लिए अनुकूल हो। हमारी नीति का उद्देश्य अपनी विकास की संभावनाओं का विस्तार करना है और विश्व में महत्वपूर्ण स्वायत्तता का स्थान पाना है। हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता हमें इस लायक बनाती है कि हम विश्व के सभी बड़े देशों के साथ परस्पर लाभ के सहयोग को आगे बढ़ा सकें।

अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध कायम करना हमारी विदेश नीति का अंतर्निहित पहलू है। हम महसूस करते हैं कि हमारी नियति भूगोल और इतिहास की वजह से जुड़ी हुई है। भारत और चीन दोनों, निकट पड़ोस में और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं।

हम देखते हैं कि विश्व आगे बढ ऱहा है और उसमें बहुध्रुवीय पहलू उभर रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि आर्थिक अंतरनिर्भरता के चलते आपस में नज़दीक आए बड़े देश परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करें। भारत और चीन को भी इसी सहयोगपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए।

मैं भविष्य के और उस भूमिका के प्रति आशावादिता के साथ देखता हू॰ जो एशिया और विश्व में परिवर्तन लाने में भारत और चीन अदा कर सकते हैं। इस आशावादिता का आधार मेरा विश्वास है कि परस्पर सहयोग को मजबूत बनाते हुए कि भारत और चीन दोनों के विकास और समृद्धि के लिए बहुत गुंजाइश है।

इतिहास बताता है कि हमारे दोनों देशों की सभ्यताएं एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान करती हुई तथा एक दूसरे को प्रभावित करती हुई, सदियों तक साथ-साथ फलती-फूलती रही हैं।

वर्ष 2005 में हमने शांति और समृद्धि के लिए जो नीतिगत और सहयोगपूर्ण भागीदारी शुरू की थी, उसका लक्ष्य बहुत सारे क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण सहयोग को बढ़ाना है। इसके साथ ही हमें उस स्थिति को भी समझना है जिसके कारण पिछले वर्षों में विवाद और समस्याएं उठी हैं और हमारे संबंधों में विषमताएं आई हैं।

हमारे दोनों देशों के बीच सीमा शान्तिपूर्ण है । दोनों देश इसे शान्ति पूर्ण बनाये रखने के लिए दृढ संकल्प हैं और हमारे विशेष प्रतिनिधि सीमा के प्रश्न को निपटाने की कोशिश में लगे हुऐ हैं। अप्रेल 2005 में, जब प्रधान मंत्री वेन जिआबाउ भारत आये थे ,तो हम सीमा के प्रश्न को निपटाने के लिए राजनैतिक मानदंडो और मार्गं निर्देयसिधान्तो पर सहमत हुए थे। हमें विश्वास है कि हम इन सिद्धांतों से इस समस्या का हल निकाल सकेंगे, जो दोनों के लिए संतोषप्रद होगा हम सीमा पार की नदियों के बारे में एक व्यवस्था बनाने पर सहमत भी हुए थे और इस काम में भी हम सफलता पाएंगे।

हम अब तक किए गए प्रयासों से संतुष्ट हैं और हमें विश्वास है कि दोनों देशों के संबन्धों में बहुत संभावनाएं हैं, जिन्हें प्राप्त किया जाएगा। हम यहाँ से किधर जा रहे हैं और इक्कीसवीं सदी के लिए हमारा क्या लक्ष्य और दृष्टिकोण है? प्रधानमंत्री वेनजिआबाउ और मैं कल इक्कीसवीं सदी के लिए साझे दृष्टिकोण के बारे में सहमत हुए थे।

पहली बात तो इस समझ की है कि भारत और चीन के सम्बन्ध न केवल दोनों देशों के लोगों के कल्याण को बल्कि क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवत्तियों को भी प्रभावित करते हैं

हम इतिहास के एसे उत्साहपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जब विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र एशिया बनता जा रहा है। बीसवीं सदी में विश्व की अर्थव्यवस्था ज्यादातर पश्चिमी देशों से जुडी हुई थी और इक्कीसवी सदी में इसका संबन्ध एशिया के साथ होगा वर्ष 2050 तक विश्व में व्यापार, आय, बचत, निवेश और वित्तीय कारोबार में आधे से जादा हिस्सा एशिया का हो सकता है

इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत और चीन, सकारात्मक दृष्टिकोण और खुशहाल का विश्व बनाने में सहयोग करें, न कि शक्तिसंतुलन और द्वेष पर आधारित बातें करें। इसके लिए भारत और चीन दोंनो को निकटता के साथ ऐसी विश्व व्यवस्था के लिए काम करना होगा, जिसमें साथ-साथ विकास हो और उस का न केवल हमारी अर्थवयस्थाओं पर और हमारे लोगों पर अनुकूल प्रभाव पडेगा, बल्कि कुल मिलाकर विश्व के अन्य देश भी इससे प्रभावित होंगे। इस सिलसिले में मैं उन क्षेत्रो का जिक्र करना चाहूंगा जिनपर भविष्य में अधिक ध्यान देना होगा।

सबसे पहले हमें भारत और चीन के बीच -ज्ञान के अन्तर को पाटना होगा। एक दूसरे के बारे में सही जानकारी लिए हमें लगातार और प्रयास करने होंगे। यह बात केवल हमारी संस्कृति और इतिहास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समसमयिक घटनाओं पर भी लागू होती हे। गलत धारणा और दुराग्रहों को दूर करने के लिए हमें लोगों के बीच आपसी सम्पर्क बढाना होगा। बुद्धिजीवियों ,मीडिया तथा सरकारी पेशवर लोगों के बीच तथा संस्कृति और कला के क्षेत्रों में विचारों का आदान -प्रदान करना होगा।

दूसरे, हमें अनेक व्यावहारिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना होगा। इसमें एक-दूसरे के राष्ट्रीय विकास के अनुभवों से सीखना भी शामिल है। भौतिक बुनियादी ढांचों के विकास, कृषि क्षेत्र से बाहर उपयोगी रोजगार जुटाने और गरीबी समाप्त करने के चीन के अनुभवों और उसकी सफलताओं से हम सीखना चाहेंगे। अन्य उपयोगी क्षेत्र जिनमें पर्याप्त सहयोग संभव है, वे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, संस्था निर्माण, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन।

तीसरे, व्यापार और कारोबार के क्षेत्रों में हमें एक-दूसरे की संपूरक क्षमताओं का फायदा उठाना चाहिए। भारत का बढता उपभोक्ता बाजार, कुशल मानव संसाधन और सॉपऊटवेयर के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ-साथ चीन का अपना बड़ा बाजार, उसकी विनिर्माण के क्षेत्र में दक्षता और कम लागत में निर्माण की क्षमता, ये बातें हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को पर्याप्त विकास का आधार दे सकते हैं। चीन पहले ही भारत के सबसे बड़े व्यापार साझीदारों में दूसरे नंबर पर है। कल हम इस बात पर सहमत हुए थे कि वर्ष 2010 तक हमारा आपसी व्यापार बढक़्र 60 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाय।

वस्तुओं के व्यापार और सेवाओं तथा पूंजीनिवेश और ज्ञान की दृष्टि से एशिया पहले से कहीं ज्यादा एकीकृत है। पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन और अन्य मंचों पर हम खुली समग्र आर्थिक व्यवस्था के लिए कई रचनात्मक विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, जो हिन्द महासागर से प्रशान्त महासागर के क्षेत्र के लिए उपयोगी हों। इस उद्देश्य के लिए हम चीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं पहले भी एशियाई आर्थिक समुदाय की चर्चा कर चुका हूं और मुझे खुशी है कि इस दिशा में प्रगति हो रही है।

इन प्रयासों को हम आगे बढा़एंगे और एशियाई तरीके से आगे बढा़एंगे-यानि एक-दूसरे का विरोध करते हुए नहीं बल्कि आपसी विश्वास और सहमति के साथ। यह केवल शांति के वातावरण में ही संभव है कि एशिया में समृद्धि कायम रहे। इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और चीन को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

विश्व स्तर पर और अधिक लोकतांत्रिक विश्वव्यवस्था कायम करने तथा विश्व समस्याओं को हल करने में बहुस्तरीय प्रयासों की दिशा में हमारे दोनों देशों को आगे रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वे आज की वास्तविकता को परिलक्षित नहीं करती और उनका लोकतंत्रिकरण होना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं के दोहा विकास दौर के सफलतापूर्वक संपन्न होने में दोनों देशों के बीच सहयोग रहा, वह एक उपयोगी अनुभव है। इससे हम इस वार्ता में विकास के पहलू को केन्द्रीय स्थान दिला सके हैं, जैसा कि होना चाहिए था। इस अनुभव से हम यह महसूस करते हैं कि विश्व भर में और खुले तथा समतापूर्ण व्यपार और वित्तीय कारोबार के लिए हमें और जोरदार प्रयास करने चाहिए।

पर्यावरण, मानवता की सांझी विरासत है। कुछ देशों ने धरती के संसाधनों का दुरूपयोग करते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, पर इस कारण से हमारे लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने से वंचित रह जायें, ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसलिए समस्याओं को सुलझाने में जिम्मेदारी उचित रूप से बांटी जानी चाहिए और इसमें ऐतिहासिक भूलों का भी ध्यान रखना होगा। हाल में संपन्न हुए बाली सम्मेलन में इस आधार पर भारत और चीन के बीच भविष्य में होने वाले सहयोग का ताना बाना मिलता है। भारत और चीन को इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहना चाहिए।

भारत और चीन में जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, उससे ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके, कि हम ऊर्जा की उपलब्धता के साधनों का विस्तार करें और ऊर्जा सुरक्षा के लिए उपयोगी नीतियां बनाएं। संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास के जरिए हम स्वच्छ तथा कम ऊर्जा की खपत वाली टेक्नोलॉजी का मिलकर विकास कर सकते हैं। भारत, चीन सहित विश्व के अन्य देशों से असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा रखता है।

एक और क्षेत्र, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वह खाद्य सुरक्षा का है। खाद्य उत्पादन और इसकी कीमतों बारे में विश्व में जो प्रवृति दिखाई दे रही है तथा खपत के जो तरीके बदल रहे हैं, उनसे खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और इनकी कीमतों पर लगातार दबाव बढ़ेगा। ये प्रवृत्तियां हमारे सामने बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं कि हम आने वालें वर्षों में अपनी

खाद्य अर्थव्यवस्था का किस तरह प्रबंधन करते हैं। हमारे हित एक समान हैं और कृषि तथा अर्थव्यवस्था के विकास में हम जो नीतियां बनाते हैं, उनके बारे में हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं।

विकास के रास्ते में शायद सबसे बड़ा खतरा उग्रवाद के सभी रूपों से है, चाहे वे धर्म के परदे में हों, या ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के नाम पर हो। हमारे पड़ोस में हाल में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे फिर से इस बात की जरूरत सामने आयी है कि हमें आतंकवाद और उग्रवाद के सभी रूपों का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। भारत और चीन बड़े और विविध समाजों वाले देश है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा सहिष्णुता के लाभों को ठीक तरह से दर्शा सकते हैं। असहिष्णुता और संकीर्णता सभी सभ्य देशों के लिए खतरा है।

भारत और चीन के संबंधों में और अधिक विकास, सांझी जिम्मेदारी से आ सकता है। हमारी सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लेकिन इसके लिए हम आपकी तरफ भी देखते हैं, आप लोग जो चीन के बुद्धिजीवी, विचारक और विद्वान हैं, कि आप भारत के बुद्धिजीवियों, विचारकों और विद्वानों के साथ मिलकर काम करें और रास्ता दिखायें। विचारों के उन्मुक्त आदान-प्रदान और भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को समझने से ही हमारे दोनों देश हमारी सभ्यताओं के संपर्कों को आदर्श रूप दे सकते हैं।

* * * * * * *